राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com
वर्ष 3 अंक 139
मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 27 अक्टूबर 2019
दैनिक जागरण
www.jagran.com
पृष्ठ 16

शुभ दीपावली

यह प्रकाश पर्व हम सबके जीवन को सुख, समृद्धि, सद्भाव से आलोकित कर राष्ट्र को समग्र उत्थान की ओर ले जाए और सर्वत्र शुभ का संचार करे, इस आशा के साथ जागरण परिवार की ओर से आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रधान संपादक

शुभ मुहूर्त

रविवार शाम 6:46 से 8:42 बजे तक

अवकाश सूचना

आपके साथ दैनिक जागरण परिवार भी 27 अक्टूबर, रविवार को दीपावली की खुशियों में शामिल होगा। इसलिए अगला अंक मंगलवार यानी 29 अक्टूबर को प्रकाशित होगा।

मुख्य महाप्रबंधक

गिनीज बुक में दर्ज हुआ अयोध्या का दीपोत्सव

जागरण संवाददाता, अयोध्या

शनिवार को अयोध्या स्थित राम की पैड़ी दीयों के अनुपम सौंदर्य से आलोकित हो उठी। यहां एक साथ जलते चार लाख दस हजार दीपों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर दीपोत्सव के तीसरे संस्करण को भी ऐतिहासिक बना दिया। यह ऐसा नजारा था जिसे हर कोई अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था।

फिजी की संसद की डिप्टी स्पीकर वीणा भटनागर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य मंत्रियों की मौजूदगी के बीच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने इस कीर्तिमान को कैद किया। गिनीज बुक के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रमाणपत्र भी सौंपा। राम की पैड़ी के साथ ही अयोध्या के अलग-अलग स्थानों पर कुल मिलाकर 6.11 लाख दीपों को जलाया गया। गत वर्ष तीन लाख 11 हजार दीयों के एक साथ जलने का रिकार्ड बनाया गया था। (पेज-5 भी देखें)

भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या शनिवार को दीपोत्सव पर लाखों दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। यहां राम की अयोध्या वापसी की त्रेतायुगीन झलक दिखाई दी। राम की पैड़ी पर चार लाख दस हजार दीप जलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। यद्यपि यहां पांच लाख 51 हजार दीप जलाए जाने की योजना थी। हृदेश चंदेल

सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद देश अपना सत्व भूल गया था और आजादी के बाद जिस सत्व को तत्काल जगाने की आवश्यकता थी उसे जागृत होने में 70 वर्ष लग गए। आश्चर्य है कि पहले की सरकारें अयोध्या से डरती थीं, लेकिन मैं ढाई साल में डेढ़ दर्जन बार यहां आ चुका हूं।
- योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम

शिवसेना ने मांगी 50-50 की गारंटी

सियासत ▸ फड़नवीस बोले, भाजपा नेतृत्व वाला गठबंधन ही देगा मजबूत सरकार

उद्धव ने कहा, पहले से तय बातें पूरा करने के लिए आगे आएं अमित शाह

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र में सरकार के गठन से पहले शिवसेना ने अपने तेवर और सख्त कर लिए हैं। पार्टी ने ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद और बराबरी के मंत्रालय के वादे पर भाजपा से लिखित आश्वासन मांगा है। इस पर सहमति न बनने की स्थिति में उद्धव ठाकरे ने दूसरे विकल्प खुले होने के संकेत भी दे दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसके नेतृत्व वाला गठबंधन ही राज्य में स्थिर और मजबूत सरकार देगा।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास 'मातोश्री' पर पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की शनिवार को बैठक हुई। करीब घंटे भर चली बैठक के बाद ठाणे से चुनकर आए विधायक प्रताप सरनाईक ने मीडिया से कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एवं मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के साथ उद्धव ठाकरे की बातचीत में 50-50 के फार्मूले पर फैसला हुआ था। ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद उसी फार्मूले का हिस्सा था। अब जब भाजपा इस पर लिखित आश्वासन देगी तभी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।

सरनाईक के मुताबिक बैठक में आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठी। अपने विधायकों की बात से सहमति जताते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि भाजपा हमारी बात नहीं मानती, तो हमारे पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं। संभवतः दूसरे विकल्पों से उद्धव ठाकरे का आशय कांग्रेस-राकांपा के साथ सरकार बनाने का है।

राकांपा का समर्थन से इन्कार : हालांकि, पीटीआइ के मुताबिक राकांपा प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को फिर कहा कि उनकी पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। उनकी पार्टी शिवसेना को सरकार बनाने के लिए समर्थन नहीं देगी। वहीं, कांग्रेस नेता विजय वाडेट्टीवार ने भी कहा कि उनकी पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। लेकिन अगर शिवसेना सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगती है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

दिवाली बाद शुरू होगी सरकार बनाने की प्रक्रिया : दूसरी ओर, दिवाली समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फड़नवीस ने कहा कि भाजपा, शिवसेना और अन्य सहयोगी दलों आरपीआइ, आरएसपी, शिव संग्राम के गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसको लेकर किसी को तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। 30 अक्टूबर को विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और उसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

(संबंधित खबरें पेज-4 पर)

हर किसी को इच्छा व्यक्त करने का हक

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सीएम पद पर शिवसेना के दावे पर कहा कि हर किसी को अपनी इच्छा व्यक्त करने का हक है। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने कहा था कि शिवसेना सत्ता में समान भागीदारी की जो बातें कर रही है, उसके बारे में पार्टी को कुछ नहीं पता।

शिवसेना का दो निर्दलीयों के समर्थन का दावा

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक नागपुर के रामटेक से निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल और भंडारा से निर्वाचित नरेंद्र भोंडेकर ने शनिवार को उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवसेना ने दावा कि दोनों ने पार्टी को समर्थन देने का प्रस्ताव किया है।

हरियाणा में आज शपथ लेंगे मनोहर लाल और दुष्यंत

मनोहर लाल को चंडीगढ़ में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मिठाई खिलाकर बधाई देते केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद। प्रेट्र

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दीपावली के दिन रविवार को अपने दूसरे कार्यकाल की नई पारी की शुरुआत करेंगे। शनिवार को केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में उन्हें सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। समर्थन देने वाली जननायक जनता पार्टी के संयोजक दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ रविवार को डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करेंगे। अनिल विज और कंवरपाल गुर्जर के भी उनके साथ शपथ लेने की संभावना है। (पेज-4)

देश में पहली बार हुआ 'सिस्टिक हायग्रोमा' का सफल ऑपरेशन

- राजस्थान के बूंदी स्थित सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को मिली कामयाबी
- डॉक्टर का दावा-दुनिया में ऐसे सात ही ऑपरेशन किए जाने का रिकार्ड

जागरण संवाददाता, जयपुर

देश में पहली बार सिस्टिक हायग्रोमा (एक तरह की गांठ) का सफल ऑपरेशन किया गया। राजस्थान के बूंदी स्थित सरकारी अस्पताल में दो साल की बच्ची खुशी का ऑपरेशन करने में डॉक्टर को कामयाबी मिली है। उनका दावा है कि दुनिया में इस तरह के अब तक महज सात ऑपरेशन का ही रिकॉर्ड है। एक सरकारी अस्पताल में इस तरह का ऑपरेशन किए जाने पर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को सम्मानित किया जाएगा।

बूंदी के जिला अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉ. अनिल सैनी ने बताया कि दो साल की बच्ची खुशी के बाएं हाथ की कलाई से कोहनी के बीच 16.50 सेंटीमीटर लंबी और 9.50 सेंटीमीटर चौड़ी गांठ थी। यह गांठ उसके जन्म से ही थी, जो धीरे-धीरे बड़ी होती गई। इससे उसका हाथ भारी हो गया। वह हाथ हिला भी नहीं पा रही थी। इस पर उसके पिता 14 अक्टूबर को अस्पताल उसको लेकर आए तो जांच में सामने आया कि उसके हाथ में इंफेक्शन हो गया है।

सोनोग्राफी में सामने आया कि बच्ची दुर्लभ बीमारी सिस्टिक हायग्रोमा से पीड़ित है। उन्होंने इस बारे में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में प्रिंसिपल डॉ.सुधीर भंडारी, अधीक्षक डॉ. डीएस मीणा और सर्जरी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ.जीवन कांकरिया से चर्चा की। इसके बाद बच्ची का बूंदी के अस्पताल में ही ऑपरेशन करने का फैसला लिया। 25 अक्टूबर को उन्होंने सफल ऑपरेशन किया गया। बच्ची अब पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने देश में सिस्टिक हायग्राम का पहला ऑपरेशन करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 80 फीसद मामलों में यह रोग गले-चेहरे पर और 20 फीसद छाती, पेट एवं पैर में होता है।

डॉक्टर अनिल सैनी ने बताया कि लसिका तंत्र (लिम्फेटिक सिस्टम) के असामान्य विकसित होने के कारण यह बीमारी हो जाती है। इसमें गांठ धीरे-धीरे बड़ी होती जाती है। यदि यह बीमारी हाथ में है तो यह पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। हाथ का मूवमेंट ही खत्म नहीं होता है बल्कि वह काला भी पड़ जाता है।

बूंदी के अस्पताल में सिस्टिक हायग्रोमा रोग का ऑपरेशन करने वाले डॉ. अनिल सैनी। जागरण

रविवार विशेष

मोदी ने धोए थे इनके पांव, धुलने लगा समाज का मैल

बांदा : कुंभ मेला के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन स्वच्छता कर्मियों के पैर धोकर प्रभावी सामाजिक संदेश दिया था, उनके गांवों में सामाजिक बदलाव की बयार बह चली है। आइये, इस दिवाली हम भी बदलें अपनी सोच। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

सारधा और रोजवैली कांड में नौ पुलिस अफसरों को नोटिस

कोलकाता : सारधा और रोजवैली चिटफंड घोटाले में सीबीआइ ने आइपीएस अधिकारी दमयंती सेन और वकार रजा समेत नौ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इनसे चार नवंबर से बाद पूछताछ होगी। ये अफसर कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अगुआई में गठित एसआइटी में बतौर जांच अधिकारी शामिल थे।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

मौसम विभाग ने दी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

नई दिल्ली : मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तथा नगालैंड में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, तटवर्ती कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा केरल में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के कोंकण बेल्ट में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

अस्पताल में भर्ती नवाज शरीफ को हार्ट अटैक, हालत गंभीर

इस्लामाबाद : अस्पताल में भर्ती पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हार्ट अटैक आने का दावा किया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह दावा शनिवार को पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर और शरीफ के वकील ने किया। जबकि अस्पताल प्रशासन ने बताया कि शरीफ को उपचार के दौरान एंजाइना अटैक से जूझना पड़ा था।

भारत को मैन्यूफैक्चरिंग में मदद को चीन तैयार

- आरसेप पर भारत को मनाने के लिए पड़ोसी ने चला दांव
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग सुधरने का यह असर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अगले शुक्रवार से बैंकॉक (थाइलैंड) में होने वाली आरसेप की बेहद अहम बैठक से ठीक पहले चीन ने भारत को लुभाने की कोशिश की है। नई दिल्ली में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ औद्योगिक और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा सहयोग करने को तैयार है जो दोनो देशों के लिए फायेदमंद साबित होगा। इसी तरह का प्रस्ताव चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कुछ ही दिनों पहले मामल्लपुरम में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अनौपचारिक बैठक में रखा था। अब नई दिल्ली में चीन के राजदूत ने इसे आगे बढ़ाया है। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में बड़ा सुधार हुआ है। वीडोंग ने वैसे तो इस प्रस्ताव को भारत की रैंकिंग में इसी सुधार से जोड़ा है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे असली वजह आरसेप के लिए भारत को मनाना है।

दूसरी तरफ भारत ने आयात बढ़ने व घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं को देखते हुए फूंक-फूंककर आगे बढ़ने की रणनीति अख्तियार कर ली है। भारत की चिंताओं को देखते हुए चीन बार-बार औद्योगिक व मैन्यूफैक्चरिंग सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जानकारों का मानना है कि चीन बेहतर समझता है कि आरसेप को लेकर भारत की तमाम चिंताओं की जड़ में दरअसल चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा है। यही वजह है कि चीन इस समझौते के जरिये भारत के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश का प्रस्ताव दे रहा है।

पिछले वर्ष भारत व चीन का द्विपक्षीय कारोबार 95.54 अरब डॉलर का था। लेकिन चीन के पक्ष में व्यापार संतुलन 53 करोड़ रुपये का था यानी चीन जितना आयात भारत से करता है उससे 53 अरब डॉलर का ज्यादा निर्यात करता है। मोदी और चिनफिंग में जिन मुद्दों पर ज्यादा बातचीत हुई यह उनमें सबसे महत्वपूर्ण था। दोनो नेताओं ने आयात व निर्यात का फासला कम करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है। लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है और इसका असर जमीन पर दिखाई देने में दो-तीन वर्ष का समय लग सकता है। वुहान में मोदी व चिनफिंग के मुलाकात के बाद चीन ने भारत से चावल, दवाई और कुछ कृषि उत्पादों के आयात को मंजूरी दी है। लेकिन इसका कारोबार के डाटा पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है।

क्या है आरसेप : रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप(आरसेप) आसियान के 10 सदस्य देशों और छह अन्य देशों (भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड) के बीच होने वाला एक मुक्त व्यापार समझौता है। वर्ष 2012 से ही इसके लिए बात हो रही है और वर्ष 2018 में ही इस पर सहमति बनने व हस्ताक्षर होने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन शुरुआत में इस समझौते के प्रति उत्साह दिखाने के बाद भारत का रुख अब बदल गया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि दूसरे सभी सदस्य देश यह कहने लगे हैं कि भारत की वजह से ही एफटीए मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। इसे सबसे ज्यादा चीन की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है।

ट्रंप की बढ़ी मुश्किल, रूसी दखल मामले की रिपोर्ट संसदीय समिति को दी जाएगी

- अमेरिकी अदालत का आदेश डेमोक्रेट पार्टी की बड़ी जीत, आगे बढ़ेगी महाभियोग की कार्यवाही

वाशिंगटन, एजेंसियां : अमेरिका की एक अदालत ने न्याय विभाग को रूसी दखल मामले में विशेष वकील रॉबर्ट मूलर द्वारा की गई जांच से जुड़ी गुप्त जानकारियां संसदीय समिति से साझा करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले को डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी जीत माना जा रहा है। वह इन जानकारियों का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच में करना चाहती है।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में नियुक्त मुख्य अमेरिकी जिला न्यायाधीश बेरिल हॉवेल ने न्याय विभाग को 30 अक्टूबर तक मूलर की जांच से जुड़ी जानकारियां संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की समिति को उपलब्ध कराने को कहा है। न्याय विभाग की एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग कोर्ट के निर्णय की समीक्षा कर रहा है। हॉवेल के आदेश में ग्रैंड जूरी का संशोधित दस्तावेज भी शामिल है, जिसका मूलर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। दस्तावेज का यह हिस्सा डेमोक्रेट सांसद अभी नहीं देख पाए हैं।

75 पन्नों के फैसले में जज हॉवेल ने प्रशासन के कई तर्कों को खारिज कर दिया। उन्होंने न्याय विभाग के उस तर्क को भी गलत करार दिया, जिसमें उसने कहा था कि वह मौजूदा कानून के तहत ग्रैंड जूरी के दस्तावेजों को नहीं उपलब्ध करा सकता। ह्वाइट हाउस और रिपब्लिकन समर्थकों ने तर्क दिया कि औपचारिक वोट के बिना महाभियोग गैरकानूनी है। इस पर हॉवेल कहा कि वास्तव में सदन में प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं है। जज ने न्याय विभाग के इस तर्क को भी खारिज कर दिया है कि मौजूदा कानून के तहत महाभियोग न्यायिक कार्यवाही है ही नहीं, जिसके लिए सूचना दी जा सके।

इस महीने की शुरुआत में सुनवाई के दौरान न्याय विभाग के वकील ने दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने का विरोध किया था। उसने कहा था कि डेमोक्रेट सांसदों के पास मूलर की जांच से संबंधित पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध हैं। उनके पास एफबीआइ द्वारा गवाहों से लिए गए बयान की कॉपी भी उपलब्ध है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एएफपी

ट्रंप के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई रिपब्लिकन नेशनल कमेटी पेज>>13

नया कश्मीर

आतंकियों की बंद की धमकी के बावजूद शनिवार को श्रीनगर में बाजारों में बढ़ी रौनक, सुबह-शाम खुलने वाले बाजार दोपहर में भी खुले, पूरे कश्मीर में नजर नहीं आई कोई पाबंदी

लाल चौक की रंगत ने दिया आतंकियों को जवाब

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

केंद्र सरकार द्वारा पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित राज्यों में पुनर्गठन के बाद हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इसकी बानगी शनिवार को श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर देखने को मिली। यहां दोपहर को भी दुकानें खुलीं, जहां खरीदारों की भीड़ उमड़ी। बाजारों में नजर आई यह रौनक आतंकियों को जवाब मानी जा रही है जो जबरन बंद लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं।

कश्मीर का नजारा तेजी से बदल रहा है। यहां अब न कोई पाबंदी है और न ही कहीं कंटीले तार नजर आ रहे हैं। वहीं, चौक को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर पूरे दिन जाम लगा रहा। पिछले कई दिनों से आतंकी संगठन तरह-तरह से लोगों को धमकाने में लगे हैं। वे न केवल सेब व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि स्कूल तक जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शनिवार को जिस तरह लाल चौक समेत वादी के विभिन्न इलाकों में दुकानें खुलीं और लोगों ने जमकर खरीददारी की उससे उनके मंसूबे नाकाम होते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि सड़कों पर निजी वाहन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सार्वजनिक वाहन काफी कम दिख रहे हैं।

अब तक सिर्फ सुबह और शाम को खुलने वाले कई प्रमुख बाजार शनिवार को दोपहर को भी खुले रहे। रेहड़ी वालों की संख्या भी बीते दिनों की तुलना में अधिक रही। बड़ी बात यह कि सुबह से ही आम लोगों और निजी वाहनों की सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई। इतना ही नहीं, हाईवे और श्रीनगर को वादी के विभिन्न शहरों से जोड़ने वाली सड़कों पर टैक्सियां भी चलीं। सभी सरकारी कार्यालय और बैंक खुले रहे। हालांकि नागरिक सचिवालय बंद रहा। वहां सिर्फ जम्मू के लिए रिकार्ड लेकर जाने वाले ट्रक और संबंधित कर्मी ही नजर आए। बनिहाल-बारामुला रेल सेवा लगातार 81वें दिन भी ठप रही।

पूरे कश्मीर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे : प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सभी प्रमुख सड़कों और चौराहों पर पुलिस व अर्ध सैनिक बलों को तैनात किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वादी में शनिवार को स्थिति पूरी तरह शांत और नियंत्रित रही।

श्रीनगर के लाल चौक का यह दृश्य कश्मीर में बदलाव की तस्वीर पेश करता है। कभी जिहादी तत्वों का गढ़ रहा लाल चौक अब व्यस्त दिख रहा है। अब न कोई पाबंदी है और न कहीं कंटीले तार। केवल दिख रही है तो नए कश्मीर की तेजी से विकास की राह पर रफ्तार भरने की ललक। कामरान रशीद बट

गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान की नहीं की जा सकती वसूली : कोर्ट

- सेना की इंजीनियरिंग सर्विस में सेवा दे चुके रिटायर अधिकारी से रिकवरी गलत ठहराई गई
- कोर्ट ने कहा, सिविल कोर्ट को इस प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में सेवा दे चुके जनक राज को विभाग की गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर रोक के खिलाफ दायर अपील पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में कर्मी ने कोई फर्जीवाड़ा कर अतिरिक्त राशि नहीं ली है बल्कि विभाग की गलती से भुगतान हुआ है जिसकी रिकवरी नहीं की जा सकती है।

केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि जनक राज को उसकी सेवा अवधि के दौरान 32 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान किया गया था जिसकी रिकवरी उनके जीपीएफ से की गई है। इसके खिलाफ जनक राज ने सिविल कोर्ट में अपील दाखिल की थी और सिविल कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया। फैसले के खिलाफ अपीलीय कोर्ट में अपील की गई, लेकिन वहां भी अपील खारिज कर दी गई। बाद में केंद्र सरकार ने सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से अपील की थी। साथ ही सिविल कोर्ट को इस तरह के मामलों में सुनवाई के लिए अधिकृत न होने की दलील दी थी। केंद्र सरकार की दलील थी कि इस मामले की सुनवाई केवल कैट में की जा सकती है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि सिविल कोर्ट को अधिकार है कि वह इस तरह के मामलों की सुनवाई कर सकता है। जनक राज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में थे, ऐसे में सिविल कोर्ट का फैसला सही है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अतिरिक्त भुगतान के लिए न तो कोई साजिश रची गई थी और न ही किसी प्रकार की धोखाधड़ी। ऐसे में यह पूरी तरह से विभाग की गलती का नतीजा है।